भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2234

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में स्वास्थ्य सेवा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

†2234. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में सुधार के लिए उक्त राज्य को आवंटित केंद्रीय योजनाओं और निधियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत उक्त राज्य में स्वीकृत या निर्मित नए एम्स, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल या स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने राज्य में गहन देखभाल क्षमता, निदान और स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता में कमियों का आकलन किया है; और
(ङ) उक्त राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और आपातकालीन तैयारियों को और बढ़ाने के लिए भविष्य की क्या रूपरेखा या प्रस्ताव विचाराधीन हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने, उनका रखरखाव करने और स्थापित करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने और स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार लाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में, विगत कुछ वर्षों में विभिन्न पहल की गई हैं और प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सुधार किया गया है, जैसा कि निम्नवत दिया गया है:

(i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संसाधन सीमा के भीतर कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, स्वास्थ्य अवसंरचना सहित उनकी स्वास्थ्य

सेवा प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को मज़बूत करने के लिए राज्यवार निधि आवंटन नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744.

(ii) पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की योजना अवधि के दौरान 708 शहरी-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), 38 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला (आईपीएचएल) और 37 गहन परिचर्या ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण का प्रावधान किया गया है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 1656.32 करोड़ रुपये है।

(iii) तमिलनाडु राज्य के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-XV) के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पाँच वर्ष की अवधि के लिए 4249.42 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 3316.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें 842 भवन रहित एसएचसी, 258 भवन रहित पीएचसी, 105 भवन रहित सीएचसी, 386 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों और 1207 शहरी-एएएम की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए पूंजीगत लागत भी शामिल है।

(iv) ईसीआरपी-II के तहत, बाल चिकित्सा परिचर्या, बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र, प्रीफैब इकाइयों के प्रावधान द्वारा अतिरिक्त बिस्तरों की वृद्धि, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रो में आईसीयू बिस्तरों की वृद्धि, 50 और 100 बिस्तरों वाले फील्ड अस्पतालों, रेफरल परिवहन और चिकित्सा गैस पाइपलाइन प्रणाली के साथ तरल चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। तमिलनाडु राज्य ने वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 798.94 करोड़ रुपये जारी किए, जिनका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है।

टेलीकंसल्टेशन, मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू), राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं आदि के माध्यम से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, रेफरल प्रणाली सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुँच बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

(ग): तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, मदुरै जिले में एम्स स्थापित है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निधि (एनएचएम) के माध्यम से 19 उप-जिला अस्पतालों को जिला अस्पतालों में उन्नयन किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएचएम और स्वास्थ्य के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान द्वारा समर्थित, राज्य भर में 708 शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(घ) और (ङ): स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, अंतराल का आकलन और स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तथपि, मंत्रालय ने अंतराल का आकलन करने और देश भर में जन स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए कई उपाय किए हैं। जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं को बढ़ाने के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानक 2022 प्रस्तुत हैं। इसके अंतर्गत तमिलनाडु ने गहन परिचर्या निदान और मानव संसाधन में कमियों की पहचान करने के लिए ओडीके टूल किट और डैशबोर्ड का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा सुविधा केंद्रों का 100% मूल्यांकन किया है। इसके अलावा, मंत्रालय और सामान्य

समीक्षा मिशन (सीआरएम) द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें, क्षेत्रीय दौरे/एकीकृत निगरानी दौरे भी कमियों का आकलन करने में मदद कर रहे हैं।

इसके अलावा, निदान सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 385 बीपीएचयू और 38 आईपीएचएल स्थापित किए गए हैं। गहन परिचर्या क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए 20 सुविधा केंद्रों को विशेष टीएईआई केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया गया है। तमिलनाडु के भविष्य के रोडमैप में गहन देखभाल क्षमता में वृद्धि, मिशन मोड में कैंसर परिचर्या का प्रबंधन, आपातकालीन तत्परता और प्राथमिक, मध्यम और आपातकालीन परिचर्या में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है।

******